



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072024-255104
CG-DL-E-03072024-255104

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, रविवार, जून 30, 2024/आषाढ 9, 1946

No. 174]

NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 30, 2024/ASHADHA 9, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2024

मामला सं. सीवीडी (एसएसआर) - 01/2024

विषय: इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कांटीन्यूअस कॉस्ट कॉपर वायर रॉड" के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

फा. सं. 07/07/2024-डीजीटीआर:—इंडियन प्राइमरी कॉपर प्रोड्यूसर एसोसिएशन (जिसे आगे "आईपीसीपीए" या "आवेदक" कहा है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान उन पर प्रतिसंतुलनकारी का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "सीवीडी नियमावली या नियमावली भी कहा गया है) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कांटीन्यूअस कॉस्ट कॉपर वायर रॉड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया है।

2. अधिनियम की धारा 9 (6) और सीवीडी नियमावली के नियम 24(3) के अनुसार लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को यदि पहले नहीं हटाया जाए तो वह उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्ष समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित होता है कि क्या उक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति

सब्सिडीकरण और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसी के अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है और क्या शुल्क की समाप्ति से सब्सिडीकरण और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

3. सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 13 के अनुसार इंडोनेशिया और मलेशिया की सरकार के अधिकारियों के साथ 13 जून, 2024 को और थाईलैंड सरकार के अधिकारियों के साथ 14 जून, 2024 को जांच शुरूआत पूर्व विचार-विमर्श किया गया था। वियतनाम सरकार ने जांच शुरूआत पूर्व चर्चाओं में भाग नहीं लिया। उन्होंने यह भी सूचित किया कि यदि उनके पास वर्तमान जांच संबंधी कोई अन्य टिप्पणी होगी तो वे उसे लिखित में भेजेंगे और यदि निर्णायक समीक्षा जांच शुरू होती है तो डीजीटीआर के साथ पूरा सहयोग करेंगे। इंडोनेशिया सरकार ने यह अनुरोध किया है कि कथित सब्सिडी कार्यक्रमों को न तो लिया गया और न ही वह इंडोनेशिया कांटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर रॉड उत्पादकों पर लागू होते हैं। मलेशिया की सरकार ने बताया है कि निर्णायक समीक्षा के जांच के दायरे के मूल जांच का पालन करना चाहिए और वर्तमान जांच में नई सब्सिडियों पर विचार नहीं करना चाहिए। थाईलैंड की सरकार ने यह आरोप लगाया है कि सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में आवेदन में प्रदत्त साक्ष्य अपर्याप्त हैं और प्राधिकारी को वर्तमान जांच में विदेशी सब्सिडियों की जांच हेतु आवेदन के अनुरोध को अस्वीकार करना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 11.2 में यह व्यवस्था है कि "आवेदन में वह सभी सूचना होगी जो आवेदक के पास तर्कसंगत ढंग से उपलब्ध हो"। प्राधिकारी मानते हैं कि सभी कथित कार्यक्रमों की मौजूदगी, उनकी प्रतिसंतुलन योग्यता और उनसे प्राप्त लाभों की मात्रा की संगत नियमों के अनुसार जांच के जरिए विश्लेषण अपेक्षित है।

क. पृष्ठभूमि

4. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल सब्सिडीरोधी जांच 10 सितंबर, 2018 को प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम फा. संख्या 6/17/2018-डीजीएडी दिनांक 5 नवंबर, 2019 के माध्यम से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक सब्सिडीरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 01/2020-सीमा शुल्क (सीवीडी) दिनांक 8 जनवरी, 2020 के जरिए निश्चयात्मक उपाय लागू किए गए थे।
5. प्राधिकारी ने मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद के एक उत्पादक और निर्यातक मेट्रोड मलेशिया एसडीएनबीएचडी पर 2.47 प्रतिशत का प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। तथापि, उत्पादक ने प्राधिकारी द्वारा विचारित एक सब्सिडी कार्यक्रम की प्रतिसंतुलन योग्यता को सेस्टेट के समक्ष चुनौती दी थी। सेस्टेट का निर्णय था कि प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंतुलन योग्य पाया गया अन्य कार्यक्रम प्रतिसंतुलन योग्य नहीं था जिससे सब्सिडी मार्जिन न्यूनतम स्तर से कम हो गया। भारतीय उद्योग द्वारा सेस्टेट के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और यह मामला लंबित है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

6. विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा मूल जांच में परिभाषित है। प्राधिकारी ने मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद अर्थात् कांटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर रॉड को निम्नानुसार परिभाषित किया था:

"7(क)... वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सीमा शुल्क टैरिफ 7408 के टैरिफ शीर्ष के अधीन आने वाले कंटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर" है। विचाराधीन उत्पाद में कॉपर वायर शामिल है जिसमें अधिकतम क्रॉस-सेक्शनल आयाम 6 मिमी से अधिक 6 मिमी और उससे कम है। अध्याय 74 के अनुसार अध्याय नोट (च) के अनुसार, वायर का अर्थ है "कॉइल में रोलड, निकाला हुआ या खींचा हुआ उत्पाद, जिसमें एक समान ठोस क्रॉस-सेक्शन होता है जो सर्कल, अंडाकार, आयताकार (वर्ग सहित) के आकार में पूरी लंबाई के साथ होता है, समबाहु त्रिभुज या नियमित उत्तल बहुभुज ("चपटे सर्कल" और "संशोधित आयत", जिनमें से दो विपरीत पक्ष उत्तल चाप हैं, अन्य दो भुजाएं समान लंबाई और समानांतर की सीधी हैं)। एक आयताकार (वर्ग सहित), त्रिकोणीय या बहुभुज क्रॉस-सेक्शन वाले उत्पादों को उनकी पूरी लंबाई के साथ गोल कोने हो सकते हैं। ऐसे उत्पादों की मोटाई जिसमें एक आयताकार ("संशोधित आयताकार" सहित) क्रॉस-सेक्शन चौड़ाई का दसवां हिस्सा होता है। निम्नलिखित को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है":

- i. कापर जिक बेस अलाय (पीतल) या कांसे (और इसी प्रकार अलाय से बनी रॉड);
- ii. कापर वेल्ड वायर

- iii. तांबा, जिंक आधारित अलाय (पीतल) या तांबा-निकिल आधारित अलाय (कुप्रो निकेल) या तांबा-जिंक निकेल आधारित अलाय (निकेल सिल्वर) या कांसा (और समान अलाय) के बने वायर्स;
- iv. सिल्वर प्लेटेड कॉपर वायर्स;
- v. टिनसेल वायर्स;
- vi. इनेमेलड कॉपर वायर्स;
- vii. मेटल कोटेड कॉपर वायर्स;
- viii. इन्सुलेटेड कॉपर वायर्स केबल्स

7. चूंकि वर्तमान आवेदन निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए है। इसलिए पीयूसी का दायरा वही रहेगा जैसा मूल जांच में परिभाषित है।
8. इच्छुक पार्टियां पीयूसी/पीसीएन, यदि कोई हो, पर अपनी टिप्पणियाँ/प्रस्तुतियाँ दे सकती हैं, इस जांच की शुरुआत की तारीख से तीस दिनों के भीतर।

ग. समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। समान वस्तु जैसे मुद्दों पर प्राधिकारी ने पहले ही मूल जांच में जांच की है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबंधित देशों से उत्पादित और आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

10. यह आवेदन इंडियन प्राइमरी कॉपर प्रोड्यूसर एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है। भारत में संबद्ध देश के चार उत्पादक अर्थात् हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेदांता (स्टरलाइट कॉपर) लिमिटेड, कच्छ कॉपर लिमिटेड (अदानी मेटल्स) और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हैं। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वेदांता (स्टरलाइट कॉपर) लिमिटेड ने संगत आंकड़े प्रदान किए हैं। कच्छ कॉपर लिमिटेड (अदानी मेटल्स) ने आवेदन का समर्थन किया है। भागीदार कंपनियों का उत्पादन सीवीडी नियमावली 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है।

ड. सब्सिडी कार्यक्रम

11. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादक / निर्यातक संबद्ध देशों की सरकारों, उन प्रदेशों और जिलों जिनमें ये उत्पादक और निर्यातक स्थिति है, द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त कार्रवाई योग्य सब्सिडियों का लाभ लेना जारी रखे हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ऐसे अतिरिक्त कार्यक्रम या स्कीमों भी हैं जिन पर वर्तमान जांच में विचार किया जाना चाहिए।

I. मूल जांच में पहले से प्रतिसंतुलित स्कीमों

- क. इंडोनेशिया
- क. निर्यात वित्तपोषण और निर्यात ऋण के रूप में कार्यक्रम
 - i. कार्यक्रम संख्या 2: इंडोनेशिया एग्जिम से निर्यात वित्तपोषण
 - ii. कार्यक्रम संख्या 3: घाटों के लिए निर्यातकों को प्रतिपूर्ति
- ख. अधिमानी ऋण और उधार के रूप में कार्यक्रम
 - iii. कार्यक्रम संख्या 5: मंडीरी बैंक द्वारा प्रदान ऋण
 - iv. कार्यक्रम संख्या 5(क): निवेश ऋण
 - v. कार्यक्रम संख्या 5(ख): उद्यमियों को ऋण

- ग. कर प्रोत्साहन और वैट छूटों के रूप में कार्यक्रम
- vi. कार्यक्रम संख्या 7: आयात शुल्क पर छूट
- vii. कार्यक्रम संख्या 8: आयात शुल्क ड्रॉ बैक
- घ. कार्यक्रम संख्या 10: निवल कर योग्य आय में कटौती
- viii. कार्यक्रम संख्या 11: घाटों को आगे ले जाना
- ix. कार्यक्रम संख्या 12: पूंजीगत समान पर आयात कर के भुगतान का स्थगन
- x. कार्यक्रम संख्या 13: उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री और समर्थक समान पर शुल्क से छूट
- xi. कार्यक्रम संख्या 14: एसईजेड में स्थित कंपनियों के लिए कतिपय सामानों के आयात पर आय कर से छूट
- xii. कार्यक्रम संख्या 15: एसईजेड में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए आय कर में कटौती
- xiii. कार्यक्रम संख्या 17: अग्रणी उद्योग का दर्जा
- xiv. कार्यक्रम संख्या 18: सूचीबद्ध निवेशों के लिए आय कर लाभ
- xv. कार्यक्रम संख्या 19: अवकाश
- ड. पर्याप्त से कम मूल्य पर (एलटीएआर) वस्तुओं और सेवाओं के रूप में कार्यक्रम
- xvi. कार्यक्रम संख्या 21: तांबा अयस्क और सांद्रण पर निर्यात सीमाएं और अन्य संबंधित उपाय
- xvii. कार्यक्रम संख्या 22: बिजली पर वैट से छूट
- ख. मलेशिया
- क. अनुदानों के रूप में कार्यक्रम
- i. कार्यक्रम संख्या 1: बाजार विकास अनुदान
- ii. कार्यक्रम संख्या 3: टेक्नो निधि
- iii. कार्यक्रम संख्या 4: इन्नो निधि
- iv. कार्यक्रम संख्या 6: निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार
- ख. निर्यात वित्तपोषण और निर्यात ऋण के रूप में कार्यक्रम
- v. कार्यक्रम संख्या 7: निर्यात ऋण पुनः वित्तपोषण
- vi. कार्यक्रम संख्या 8: क्रेता ऋण गारंटी
- ग. कर प्रोत्साहन और वैट छूटों के रूप में कार्यक्रम
- vii. कार्यक्रम संख्या 9: अग्रणी दर्जा
- viii. कार्यक्रम संख्या 10: निवेश कर प्रक्रियाएं
- ix. कार्यक्रम संख्या 11: पुनः निवेश भत्ता
- x. कार्यक्रम संख्या 12: त्वरित पूंजीगत भत्ता
- xi. कार्यक्रम संख्या 13: समूह राहत
- xii. कार्यक्रम संख्या 14: टैरिफ संबंधित प्रोत्साहन
- xiii. कार्यक्रम संख्या 15: उद्योग निर्माण भत्ता
- xiv. कार्यक्रम संख्या 17: मलेशियाई ब्रांड के संवर्धन के लिए कर योग्य लाभ से दोहरी कटौती
- xv. कार्यक्रम संख्या 18: पूर्वी तटीय आर्थिक कोरिडोर में विनिर्माण और विनिर्माण संबंधी सेवाओं के लिए प्रोत्साहन
- xvi. कार्यक्रम संख्या 19: आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर ड्रॉ बैक

- xvii. कार्यक्रम संख्या 21: विनिर्माण कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग के लिए आयात कर और बिक्री कर से छूट
- xviii. कार्यक्रम संख्या 23: मशीनरी और उपकरण पर आयात कर और बिक्री कर से छूट
- xix. कार्यक्रम संख्या 24: कच्ची सामग्री / घटकों पर आयात कर से छूट
- xx. कार्यक्रम संख्या 25: निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए कर योग्य लाभों से दोहरी कटौती
- xxi. कार्यक्रम संख्या 27: लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रोत्साहन
- xxii. कार्यक्रम संख्या 28: बड़े हुए निर्यातों के लिए भत्ता
- xxiii. कार्यक्रम संख्या 30: अनुसंधान और विकास निधि का वाणिज्यीकरण (सीआरडीएफ)
- xxiv. कार्यक्रम संख्या 31: इन हाउस आर एंड डी के लिए कर प्रोत्साहन
- xxv. कार्यक्रम संख्या 32: अनुसंधान और विकास के लिए दोहरी कटौती

घ. अधिमानी ऋण और उधार के रूप में कार्यक्रम

- xxvi. कार्यक्रम संख्या 34: लघु और मध्यम उद्यमों को आसान ऋण
- xxvii. कार्यक्रम संख्या 35: अंतर्राष्ट्रीय खरीद केंद्र

ग. थाईलैंड

क. कर प्रोत्साहन और वैट छूटों के रूप में कार्यक्रम

- i. कार्यक्रम संख्या 2: मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट/कटौती
- ii. कार्यक्रम संख्या 3: आय कर छूट
- iii. कार्यक्रम संख्या 4: निवेश संरक्षण जोन के संबंध में छूट
- iv. कार्यक्रम संख्या 5: निर्यात के लिए उत्पादन में प्रयोग हेतु आयातित कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क से छूट
- v. कार्यक्रम संख्या 6: कच्ची या अनिवार्य सामग्रियों के लिए आयात शुल्क में कटौती
- vi. कार्यक्रम संख्या 7: पीओआई – संवर्धित कार्यकलापों के लिए कारपोरेट आय कर से छूट
- vii. कार्यक्रम संख्या 8: निवेश संरक्षण जोनों में कारपोरेट आय कर में 50 प्रतिशत की कटौती
- viii. कार्यक्रम संख्या 9: संवर्धित जोनों में परिवहन, बिजली और जल आपूर्ति की लागत में आय कर में दोहरी कटौती
- ix. कार्यक्रम संख्या 10: सुविधाओं को लगाने या निर्माण की लागत में आय कर में दोहरी कटौती
- x. कार्यक्रम संख्या 11: कर और शुल्क प्रतिपूर्ति / कर कूपन
- xi. कार्यक्रम संख्या 12: बॉर्डेड वेयरहाउस के लिए आयात / निर्यात शुल्क से छूट
- xii. कार्यक्रम संख्या 13: थाईलैंड में बिल्कुल नहीं या बहुत कम मौजूदा निवेश के साथ मूल्यवर्धन सृजित करने के लिए देश के विकास, उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग वाले कार्यकलाप हेतु संरचना में कार्यकलापों का प्रोत्साहन
- xiii. कार्यक्रम संख्या 14: उच्च प्रौद्योगिकी कार्यकलापों को प्रोत्साहन जो थाईलैंड में पहले से मौजूद काफी कम निवेश के साथ देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- xiv. कार्यक्रम संख्या 15: प्रतिस्पर्धी वृद्धि में विकास के लिए गुण आधारित प्रोत्साहन
- xv. कार्यक्रम संख्या 17: संवर्धनात्मक विशेषाधिकार
- xvi. कार्यक्रम संख्या 18: शुल्क ड्रॉ बैक

ख. मुक्त व्यापार जोन स्कीमों के अंतर्गत कार्यक्रम

- xxvii. कार्यक्रम संख्या 19: सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय x के अंतर्गत मुक्त व्यापार जोन

xxviii. कार्यक्रम संख्या 20: औद्योगिक संपदा प्राधिकार कानून के अंतर्गत निर्यात प्रसंस्करण जोन

घ. वियतनाम

क. कर प्रोत्साहन और वैट छूटों के रूप में कार्यक्रम

- i. कार्यक्रम संख्या 1: डिक्री 24 के अध्याय v के अंतर्गत आय कर वरीयता
- ii. कार्यक्रम संख्या 2: कच्ची सामग्री के लिए आयात शुल्क छूट या प्रतिपूर्ति
- iii. कार्यक्रम संख्या 3: उद्यमों के लिए कारपोरेट आय कर से छूट

ख. निर्यात वित्त और निर्यात ऋण के रूप में कार्यक्रम

- iv. कार्यक्रम संख्या 5: निर्यातकों के लिए अधिमानी ऋण
- v. कार्यक्रम संख्या 6: निर्यात संवर्धन कार्यक्रम
- vi. कार्यक्रम संख्या 7: वियतनाम डेवलपमेंट बैंक से निर्यात ऋण
- vii. कार्यक्रम संख्या 8: निर्यात आपूर्ति ऋण

ग. निर्यात वित्त और निर्यात ऋण के रूप में कार्यक्रम

- viii. कार्यक्रम संख्या 5: निर्यातकों के लिए अधिमानी ऋण
- ix. कार्यक्रम संख्या 6: निर्यात संवर्धन कार्यक्रम
- x. कार्यक्रम संख्या 7: वियतनाम डेवलपमेंट बैंक से निर्यात ऋण
- xi. कार्यक्रम संख्या 8: निर्यात आपूर्ति ऋण

घ. निवेश प्रोत्साहनों के रूप में कार्यक्रम

- xii. कार्यक्रम संख्या 9: निवेशकों के लिए ऋण अधिमानी ऋण
- xiii. कार्यक्रम संख्या 10: निवेश क्रेडिट ऋणों पर ब्याज दर
- xiv. कार्यक्रम संख्या 11: स्थापित लघु और मध्यम उद्यमों में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को निवेश सहायता
- xv. कार्यक्रम संख्या 13: वियेटिन बैंक द्वारा वित्तीय गारंटी

ड. पर्याप्त से कम मूल्य (एलटीएआर) पर वस्तुओं और सेवाओं के रूप में कार्यक्रम

- xvi. कार्यक्रम संख्या 14: डिक्री 142 के अंतर्गत और प्रोत्साहन उद्योगों या औद्योगिक जोनों में उद्यमों के लिए भूमि में वरीयता
- xvii. कार्यक्रम संख्या 15: पर्याप्त से कम मूल्य पर भूमि का सरकारी प्रावधान और भूमि तथा जल किराये से छूट या कटौती

II. नए सब्सिडी कार्यक्रम

क. इंडोनेशिया

- i. कर प्रोत्साहन और वैट छूटों के रूप में कार्यक्रम
- ii. कार्यक्रम सं. 22: अनुसंधान और विकास पर असाधारण कटौतियां

ख. मलेशिया

- i. एलटीएआर पर वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के रूप में कार्यक्रम
- ii. कार्यक्रम संख्या 37: पर्याप्त से कम मूल्य पर कॉपर कैथोड की इंडोनेशिया से खरीद
- iii. कार्यक्रम संख्या 38: पर्याप्त से कम मूल्य पर प्राकृतिक गैस का प्रावधान
- iv. कार्यक्रम संख्या 39: एलटीएआर पर बिजली का प्रावधान
- v. कार्यक्रम संख्या 40: हरित निवेश कर भत्ता

ग. थाईलैंड

- i. एलटीएआर पर वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के रूप में कार्यक्रम
- ii. कार्यक्रम संख्या 21: एलटीएआर पर इलेक्ट्रिकल बिजली का प्रावधान

घ. वियतनाम

- i. एलटीएआर पर वस्तुओं और सेवाओं के रूप में कार्यक्रम
- ii. कार्यक्रम संख्या 16: पर्याप्त से कम मूल्य पर कॉपर कैथोड की इंडोनेशिया से खरीद

12. निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी अन्य सब्सिडियों की जांच कर सकते हैं जो मौजूद पायी जाती हैं और जिनका जांच की प्रक्रिया के दौरान संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादक / निर्यातक लाभ उठा रहे हैं।

च. सब्सिडी और क्षति के जारी रहने / पुनरावृत्ति होने की संभावना

13. भारत में निर्यात कीमत से कम कीमत पर तीसरे देशों को निर्यात, संबद्ध देशों में क्षमता वृद्धि, निर्यात उन्मुखीकरण और सब्सिडीरोधी शुल्क की समाप्ति का घरेलू उद्योग के निष्पादन पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करते हुए सब्सिडीरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में सब्सिडीकरण और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं।

छ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

14. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और सब्सिडी और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी सीवीडी नियमावली के नियम 24 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार एतद्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने की क्या मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति से सब्सिडी और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। एक निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

ज. संबद्ध देश

15. वर्तमान जांच में संबद्ध देश इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम हैं।

झ. जांच की अवधि (पीओआई)

16. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 जनवरी 2023 – 31 दिसंबर 2023 (12 महीने) की है। जांच के लिए क्षति अवधि में 2020-21, 2021-22, 2022-2023 और जांच की अवधि शामिल होगी।

ञ. प्रक्रिया

17. इस निर्णायक समीक्षा जांच में फा. संख्या 6/17/2018-डीजीएडी दिनांक 5 नवंबर 2019 द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे। प्राधिकारी लागू सब्सिडीरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में सब्सिडीकरण और क्षति के जारी रहने / पुनरावृत्ति होने का संभावना विश्लेषण भी करेंगे।

18. सीवीडी नियमावली 1995 के नियम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 और 22 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ वर्तमान समीक्षा जांच पर लागू होंगे।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

19. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले समस्त पत्र ई-मेल पतों adv11-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dd17-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

20. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उत्पादकों को नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर उल्लिखित ईमेल पतों पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने के लिए वे प्राधिकारी के सरकारी वेबसाइट (<http://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें।

घ. समय सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार नोटिस प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों adv11-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dd17-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाले या निर्यातक देश से उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करें।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

26. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को एडी नियमावली 1995 के नियम 8 (2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
27. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उसमें संलग्न परिशिष्ट / अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय तथा अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
28. "गोपनीय या अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
29. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
30. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है और गोपनीयता का दावा की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।
31. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषयवस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है और एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।
32. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैरा 25 के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है।

33. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त कारण के विवरण के बिना किए गए किसी गोपनीयता के दावे को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
 34. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
 35. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।
 36. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों / उत्तर / सूचना का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें। अनुरोध/ उत्तर / सूचना के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।
- ढ. असहयोग**
37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तर्कसंगत अवधि या समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2024

Case No. CVD (SSR)-01/2024

Subject: Initiation of sunset review investigation of countervailing duty concerning imports of “Continuous Cast Copper Wire Rod” originating in or exported from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam

F.No. 07/07/2024-DGTR—Indian Primary Copper Producers’ Association (hereinafter referred to as “IPCPA” OR “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) under the provisions of the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “CVD Rules” or “Rules”) for the initiation of a sunset review investigation of countervailing duties concerning imports of “Continuous Cast Copper Wire Rod” (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) originating in or exported from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam (hereinafter referred to as the “subject countries”).

2. In terms of Section 9 (6) of the Act and Rule 24 (3) of the CVD Rules, the countervailing duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of the said countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury to the domestic industry. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether there is a need for the continued imposition of the countervailing duty, and whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury.
3. In terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, pre-initiation consultations were held with the officials of the Government of Indonesia and Malaysia on 13th June, 2024 and with the Government of Thailand on 14th June, 2024. The Government of Vietnam has not participated in the pre-initiation consultations. They further informed that in case they have any other comments on the

present investigation, they will send a written submission and fully cooperate with DGTR if the sunset review investigation is initiated. The Government of Indonesia has submitted that the alleged subsidy programs were neither availed nor are applicable to the Indonesian continuous cast copper wire rod producers. The Government of Malaysia has submitted that the scope of the sunset review investigation should adhere to the original investigation and new subsidies should not be considered in the present investigation. The Government of Thailand has alleged that the evidence provided in the application regarding subsidy programs is insufficient and the Authority should reject the request of the applicant to investigate the transnational subsidies in the present investigation. The Authority notes that Article 11.2 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures provides that "the application shall contain such information as is reasonably available to the applicant". The Authority considers that the existence of all alleged programs, their countervailability and extent of benefit therein are required to be analysed through an investigation as per the relevant rules.

A. Background

4. The original anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries was initiated by the Authority on 10th September, 2018. The Authority recommended the imposition of definitive anti-subsidy duties on the imports of the subject goods from the subject countries vide Final Finding F. No. 6/17/2018-DGAD dated 5th November, 2019. The definitive measures were imposed by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 01/2020-Customs (CVD) dated 8th January, 2020.
5. The Authority had recommended the imposition of countervailing duties of 2.47% on Metrod Malaysia SdnBhd, a producer and exporter of the product under consideration from Malaysia. However, the producer challenged before CESTAT the countervailability of one of the subsidy programmes considered by the Authority. The CESTAT held that the 'other programme' found countervailable by the Authority was not countervailable which reduced the subsidy margin below the de minimis level. The decision of CESTAT was challenged by the Indian industry before the Hon'ble Supreme Court and the matter is pending.

Product under consideration

6. The product under consideration is the same as defined in the original investigation. The Authority defined the product under consideration, i.e., continuous cast copper wire rod in the final finding of the original investigation as follows:

"7(a)..... The product under consideration in the present investigation is "Continuous Cast Copper Wire falling under tariff heading 7408 of the Customs Tariff". The product under consideration includes Copper Wire of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6 mm as well 6 mm and below. As per Chapter note (f) to Chapter 74, Wire means "Rolled, extruded or drawn products, in coils, which have a uniform solid cross-section along their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or regular convex polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). Products with a rectangular (including square), triangular or polygonal cross-section may have corners rounded along their whole length. The thickness of such products which have a rectangular (including "modified rectangular") cross-section exceeds one-tenth of the width". The following are excluded from the scope of the PUC:

i. Rods made of copper-zinc base alloys (brass) or bronze (and similar alloys);

ii. Copper weld wires;

iii. Wires made of copper- zinc based alloys (brass) or copper- nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) or bronze (and similar alloys);

iv. Silver plated copper wires;

v. Tinsel wires;

vi. Enameled copper wires;

vii. Metal coated copper wires;

viii. Insulated copper wires cables.

7. As the present application is for initiation of a sunset review investigation, the scope of the PUC remains as defined in the original investigation.
8. The interested parties may offer their comments/submissions on the PUC/ PCN, if any, within thirty days from the date of date of initiation of this investigation.

C. Like article

9. The applicant has claimed that there is no known significant difference in the product produced by the domestic industry and those exported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. The issue of like article has already been examined by the Authority in the original investigation. Therefore, the product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration produced and imported from the subject countries.

D. Domestic industry and standing

10. The application has been filed by the Indian Primary Copper Producers' Association. There are four producers of the subject goods in India, namely, Hindalco Industries Limited, Vedanta (Sterlite Copper) Limited, Kutch Copper Limited (Adani Metals) and Hindustan Copper Limited. Hindalco Industries Limited and Vedanta (Sterlite Copper) Limited have provided the relevant data. Kutch Copper Limited (Adani Metals) has supported the application. The production of participating companies constitutes a major proportion in the total domestic production in terms of Rule 2(b) of the CVD Rules, 1995.

E. Subsidy programs

11. The applicant has alleged that the producers/ exporters of the subject goods in the subject countries continue to be benefitted from actionable subsidies provided at various levels by the Governments of the subject countries, including the provinces and districts in which producers/exporters are located. The applicant has also claimed that there are additional programs or schemes that should be considered in the present investigation.

I. Schemes previously countervailed in the original investigation**A. Indonesia****a. Programmes in the form of export financing and export credit**

- i. Programme no. 2: Export financing from Indonesia EXIM Bank
- ii. Programme no. 3: Reimbursement to exporters for losses

b. Programs in the form of preferential loans and lending

- iii. Programme no. 5: Loans by Mandiri Bank
- iv. Programme no. 5(a): Investment loan
- v. Programme no. 5(b): Loans to entrepreneurs

c. Programs in the form of tax incentives and VAT exemptions

- vi. Programme no. 7: Exemption on import duty
- vii. Programme no. 8: import duty drawback

d. Programme no. 10: reduction of net taxable income

- viii. Programme no. 11: carrying forward of losses
- ix. Programme no. 12: Postponement of payment of import duty on capital goods
- x. Programme no. 13: exemption of duty on raw material and supporting goods for production
- xi. Programme no. 14: exemption from income tax on import of certain goods for companies located in SEZs
- xii. Programme no. 15: reduction in income tax for investors investing in SEZs
- xiii. Programme no. 17: Pioneer Industry Status
- xiv. Programme no. 18: income tax benefits for listed investments
- xv. Programme no. 19: tax holiday

e. Programs in the form of provision of goods and services for less than adequate remuneration (LTAR)

- xvi. Programme no. 21: export restraints and other related measures on copper ore and concentrate
- xvii. Programme no. 22: VAT exemption on electricity

B. Malaysia**a. Programmes in the form of grants**

- i. Programme no. 1: market development grant
- ii. Programme no. 3: Techno Fund
- iii. Programme no. 4: Inno Fund
- iv. Programme no. 6: export excellence award
- b. **Programs in the form of export financing and export credit**
 - v. Programme no. 7: export credit refinancing
 - vi. Programme no. 8: buyer credit guarantee
- c. **Programs in the form of tax incentives and VAT exemptions**
 - vii. Programme no. 9: pioneer status
 - viii. Programme no. 10: investment tax practices
 - ix. Programme no. 11: reinvestment allowance
 - x. Programme no. 12: accelerated capital allowance
 - xi. Programme no. 13: group relief
 - xii. Programme no. 14: tariff-related incentives
 - xiii. Programme no. 15: industry-building allowance
 - xiv. Programme no. 17: double deduction from taxable profit for promotion of Malaysian brand
 - xv. Programme no. 18: incentives for manufacturing and manufacturing-related services in East Coast Economic Corridor
 - xvi. Programme no. 19: drawback on import duty, sales tax and excise duty
 - xvii. Programme no. 21: exemption from import duty and sales tax for outsourcing manufacturing activities
 - xviii. Programme no. 23: Exemption from import duty and sales tax on machinery and equipment
 - xix. Programme no. 24: exemption from import duty on raw materials/components
 - xx. Programme no. 25: double deduction from taxable profits for promotion of exports
 - xxi. Programme no. 27: incentives for small and medium enterprises
 - xxii. Programme no. 28: allowance for increased export
 - xxiii. Programme no. 30: Commercialisation of Research and Development Funds (CRDF)
 - xxiv. Programme no. 31: tax incentives for in-house R&D
 - xxv. Programme no. 32: double deduction for research and development
- d. **Programs in the form of preferential loans and lending**
 - xxvi. Programme no. 34: soft loans to small and medium enterprises
 - xxvii. Programme no. 35: international procurement centre
- C. **Thailand**
 - a. **Programs in the form of tax incentives and VAT exemptions**
 - i. Programme no. 2: exemption/reduction of import duties on machinery
 - ii. Programme no. 3: income tax exemption
 - iii. Programme no. 4: exemptions with regard to the investment protection zone
 - iv. Programme no. 5: exemption of import duty on raw material imported for use in production for export
 - v. Programme no. 6: reduction of import duty for raw or essential materials.
 - vi. Programme no. 7: exemption of corporate income tax for BOI-promoted activities
 - vii. Programme no. 8: 50% reduction of corporate income tax in investment protection zones
 - viii. Programme no. 9: income tax double deduction of the costs of transportation, electricity and water supply in promoted zones
 - ix. Programme no. 10: income tax double deduction of the cost of installation or construction of facilities
 - x. Programme no. 11: tax and duty compensation/tax coupons
 - xi. Programme no. 12: exemption of import/export duty for bonded warehouses
 - xii. Programme no. 13: incentives for activities in infrastructure for the country's development, activities using advanced technology to create value added with no or very few existing investments in Thailand
 - xiii. Programme no. 14: incentives for high technology activities which are important to the country's development with a few investments already existing in Thailand
 - xiv. Programme no. 15: merit-based incentive for increase in competitive enhancement
 - xv. Programme no. 17: promotional privileges
 - xvi. Programme no. 18: duty drawback
 - b. **Programs under Free Trade Zones schemes**
 - xvii. Programme no. 19: Free Trade Zone under Chapter X of Customs Act
 - xviii. Programme no. 20: export processing zone under the Industrial Estate Authority Law

- D. Vietnam**
- a. Programs in the form of tax incentives and VAT exemptions**
- i. Programme no. 1: income tax preferences under Chapter V of Decree 24
 - ii. Programme no. 2: import duty exemption or reimbursement for raw material
 - iii. Programme no. 3: exemption on corporate income tax for enterprises
- b. Programs in the form of export finance and export credit**
- iv. Programme no. 5: preferential lending to exporters
 - v. Programme no. 6: export promotion programme
 - vi. Programme no. 7: export credits from Vietnam Development Bank
 - vii. Programme no. 8: export supply credits
- c. Programs in the form of export finance and export credit**
- viii. Programme no. 5: preferential lending to exporters
 - ix. Programme no. 6: export promotion programme
 - x. Programme no. 7: export credits from Vietnam Development Bank
 - xi. Programme no. 8: export supply credits
- d. Programs in the form of investment incentives**
- xii. Programme no. 9: preferential lending for investors
 - xiii. Programme no. 10: interest rate on investment credit loans
 - xiv. Programme no. 11: investment support to foreign investors investing in established small and medium enterprises
 - xv. Programme no. 13: financial guarantees by Vietin Bank
- e. Programs in the form of provision of goods and services for less than adequate remuneration (LTAR)**
- xvi. Programme no. 14: land preferences for enterprises in encouraged industries or industrial zones under Decree 142
 - xvii. Programme no. 15: government provision of land for less than adequate remuneration and exemptions or reduction from land and water rents
- II. New Subsidy Programs**
- A. Indonesia**
- i. Programs in the form of tax incentives and VAT exemptions
 - ii. Programme no. 22: Super-normal deductions on research and development expenditure
- B. Malaysia**
- i. Programs in the form of provision of goods and services for LTAR
 - ii. Programme no. 37: procurement from Indonesia of copper cathode for less than adequate remuneration
 - iii. Programme no. 38: provision of natural gas for less than adequate remuneration
 - iv. Programme no. 39: provision of electricity at LTAR
 - v. Programme no. 40: Green Investment Tax Allowance
- C. Thailand**
- i. Programs in the form of provision of goods and services for LTAR
 - ii. Programme no. 21: Provision of electricity for LTAR
- D. Vietnam**
- i. Programs in the form of provision of goods and services for LTAR
 - ii. Programme no. 16: procurement from Indonesia of copper cathode for less than adequate remuneration
12. The Designated Authority may investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers/ exporters of the subject goods in the subject countries, during the course of the investigation.
- F. Likelihood of continuation/recurrence of subsidy and injury**
13. There is *prima facie* evidence of likelihood of continuation/recurrence of subsidization and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-subsidy duty, considering third country exports at prices lower than the domestic prices in India, capacity additions in the subject countries, export orientation and likely adverse impact of cessation of anti-subsidy duty on the performance of the domestic industry.
- G. Initiation of sunset review investigation**

14. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating likelihood of continuation or recurrence of subsidization and injury to the domestic industry the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of countervailing duty on imports of the subject goods from the subject countries and to examine whether the expiry of the existing countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidy and consequent injury to the domestic industry, in accordance with Section 9 of the Act, read with Rule 24 of the CVD Rules.

H. Subject countries

15. The subject countries in the present investigation are Indonesia, Thailand, Malaysia and Vietnam.

I. Period of investigation (POI)

16. The period of investigation (POI) for the present investigation is from 1st Jan 2023 – 31st Dec 2023 (12 months). The injury period for the investigation will include 2020–21, 2021–22, 2022–2023 and the period of investigation.

J. Procedure

17. The sunset review investigation will cover all aspects of the final findings published vide F. No. 6/17/2018-DGAD dated 5th November 2019. The Authority will also undertake likelihood analysis of continuation/recurrence of subsidization and injury in the event of expiry of anti-subsidy duty in force.
18. The provisions of Rules 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 and 22 of the CVD Rules, 1995 shall be *mutatis mutandis* applicable in this present review investigation.

K. Submission of information

19. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adv11-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dd17-dgtr@gov.in and dd19-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
20. The known producers/exporters from the subject countries their government through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic producers are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email addresses mentioned hereinabove.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
23. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority <http://www.dgtr.gov.in> for any updated information with respect to this investigation.

L. Time limit

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adv11-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dd17-dgtr@gov.in and dd19-dgtr@gov.in. within thirty days (30 days) from the date of receipt of the notice as per Rule 7(4) of the CVD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.
25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.

M. Submission of information on confidential basis

26. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 8(2) of the CVD Rules, 1995 and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

27. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non- confidential versions separately.
28. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
29. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
30. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
31. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
32. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by any interested party within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of paragraph 25 of this initiation notification.
33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may, disregard such information.
35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.
36. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

N. **Non-cooperation**

37. In case any interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority